भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1741
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

सिंटर संयंत्र परियोजना में देरी का बीएसएल पर प्रभाव

1741. श्री दुलू महतोः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन को वर्ष 2019 में दी गई 400 करोड़ रुपये की सिंटर संयंत्र परियोजना अभी भी अधूरी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस परियोजना में लंबे समय से विलंब के कारण ब्लास्ट फर्नेस-। के दैनिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को भारी वित्तीय हानि हुई है।
(ग) क्या सरकार को इस मामले के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस परियोजना को पूरा करने में इतने अधिक विलंब के कारणों का स्पष्टीकरण दे सकती है और इसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के बारे में बता सकती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है; और
(च) क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी ताकि बीएसएल को और अधिक नुकसान होने से रोका जा सके?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (च): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड/बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल/बीएसएल) में सिंटर संयंत्र परियोजना का अनुबंध वर्ष 2015 में दिया गया था। हालाँकि, डिजाइन, इंजीनियरिंग और संसाधन नियोजन के लिए जिम्मेदार एक कंसोर्टियम भागीदार के गैर-कार्य निष्पादन और कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों आदि की वजह से परियोजना की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। डिफॉल्ट करने वाले कंसोर्टियम भागीदार के लगातार खराब कार्य निष्पादन के कारण, संबंधित फर्म को व्यावसायिक लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा जोखिम एवं लागत कार्रवाई भी शुरू की गई थी।

सेल/बीएसएल मौजूदा सिंटर संयंत्र की मरम्मत और डीबॉटलनेकिंग के माध्यम से अपने वर्तमान प्रचालन स्तरों के लिए सिंटर की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था। सेल/बीएसएल ने मुख्य पैकेज को पूरा करने के लिए शेष कार्यों का अनुबंध वर्ष 2025 में नई एजेंसियों को दिया है, जिसका निष्पादन शुरू हो चुका है।

परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए, डिजिटल परियोजना प्रबंधन समाधान और इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉइंग प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। सरकार के पास सेल की सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी का एक संरचित तरीका है।

******